ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **01 Dec, 2025**

Dr Abhishek Manu Singhvi, MP and Chairman, Law, Human Rights & RTI department, AICC, addressed the media at Vijay Chowk, outside Parliament House, today.

डॉ० अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा- दोस्तों, एक और इंस्टॉलमेंट आपको मिल रहा है... प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति, धमकी की राजनीति, खासतौर से निशाना बनाने का प्रयत्न श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, विघटन के मुद्दे, विदेश नीति के मुद्दे, अमेरिका से लेकर, चीन से लेकर... बांग्लादेश के मुद्दे इत्यादि-इत्यादि। अगर आपको यहां से नजर हटानी है, डायवर्ट करनी है तो यह इस प्रकार के उत्पीड़न, प्रतिशोध के मुद्दे आपको उठाने पड़ते रहेंगे।

तो मैं अभी आपको बड़े सरल तरीके से बताना चाहता हूं कि जहां कुछ हुआ ही नहीं, जहां कोई क्राइम ही नहीं है, वहां किस प्रकार से क्राइम की इजाद की जा सकती है, इसमें हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को और ईडी को एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। यह एक अजूबा है, वन ट्रिक वंडर है... यह एक ही उदाहरण है जहां बिना एक पैसे का स्थानांतरण हुए, बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति... इमूवेबल का स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है नेशनल हेराल्ड के विषय में और ऐसा यह अजूबा है कि मैं समझता हूं कि यह पहली बार वन ऑफ दी सेवन और एट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाना चाहिए।

एजेएल से शुरू करता हूं मैं... आप सब जानते हैं जानीमानी पुरानी कंपनी है, 50 वर्ष से, उससे भी ज्यादा एक मशाल लेकर कुछ आदर्शों के लिए खड़ी है नेशनल हेराल्ड। ब्रिटेन के विदेशी रूल के समय में खड़ी थी, उसके बाद खड़ी है और ऐसा होता है कई बार कि आदर्शवाद पर स्थापित संस्थाएं वाणिज्य के रूप से, आर्थिक रूप से अच्छा नहीं करती, यही हुआ नेशनल हेराल्ड... एजेएल के साथ। इन 50-55-60 सालों में उस आदर्श को ऊंचा रखने के लिए, कांग्रेस के आदर्शों को, उस मशाल को जलाते हुए रखने के लिए विभिन्न समय पर एआईसीसी ने अलग-अलग समयों पर 55-60 वर्षों के बीच में उसको लोन दिया... एजेएल

को। वो लोन एक वक्त पर 90 करोड़ हो गया था। एजेएल कंपनी है, जो सिर्फ नेशनल हेराल्ड नहीं चलाती, लेकिन जिसके पास अचल संपत्ति है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर।

तो यह निर्णय किया गया कि कैसे इस पुरानी मशाल वाली कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। उसके लिए यह आवश्यक था कि उसको ऋण मुक्त किया जाए, डेट फ्री कंपनी को जाए, जो डेट 90 करोड़ का था। इसलिए एक ऐसी चीज की गई जो हर कंपनी देश में करती है... जो ऋण होता है, उसको इक्विटी में कन्वर्ट करो, डेट इनटू इक्विटी।

यह संपत्ति है सब, इस संपत्ति का मालिकाना हक है मेरे पास, मैं हूं एजेएल। यह संपत्ति भी यहीं रहती है, एक इंच नहीं हिलती है, एजेएल भी यहीं रहता है। लेकिन एजेएल के लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरी कंपनी बनाई गई- 'यंग इंडियन'। 'यंग इंडियन' एक विचित्र कंपनी है, मैं आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन यह जो ऋण है मेरा... एजेएल का, उसको 'यंग इंडियन' को असाइन कर दिया गया, दे दिया गया... इसका मतलब हुआ कि शेयर होल्डिंग एजेएल की अधिकतर रूप से... 99% 'यंग इंडियन' के हाथ में आ गई। कोई प्रॉपर्टी मूव नहीं की, कोई रुपया मूव नहीं किया, एजेएल की कंट्रोलिंग कंपनी 'यंग इंडियन' बन गई।

अब 'यंग इंडियन' में ऑस्कर फर्नांडिस थे, मोतीलाल वोरा जी थे, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, सुमन दुबे हैं, अन्य लोग हैं, सैम पित्रोदा हैं। ये कौन हैं? ये कांग्रेस के आदर्शों से जुड़े हुए वो लोग हैं, जो इस कंपनी को, जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विशेष रूप से कंपनीज एक्ट में बनाया जाता है। उस कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि यह 'यंग इंडियन' जो अब 99% शेयर होल्ड करती है एजेएल की... वो न डिविडेंट दे सकती है, न प्रॉफिट बना सकती है। अगर प्रॉफिट बनता है, तो वो उस 'यंग इंडियन' में ही रहेगा, ना कोई इन लोगों को, डायरेक्टर्स को कोई पर्क देती है, गाड़ी-घोड़ा कुछ नहीं, ना कोई सैलरी देती है।

इस स्थिति में कहा गया है कि चूंकि एजेएल का 99% कंट्रोल 'यंग इंडियन' में चला गया, इसलिए एजेएल द्वारा होल्डिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो सब स्थानांतरित हो गईं और मनी लॉन्ड्रिंग हो गई करोड़ों रुपए की। यह विचित्रता मैं नहीं समझता कि किंडर गार्टन, कानून के विद्यार्थी से लेकर पीएचडी तक कोई समझा सकता है, लेकिन ईडी ने समझ लिया और ईडी द्वारा विश्व भर को समझाने का प्रयत्न चल रहा है।

एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको। यह अभी सब जो मैंने बोला है, यह पहले ही हो गया था, एक चार्जशीट फाइल हो गई थी। वो चार्जशीट राउज़ एवेन्यू के एक स्पेशल कोर्ट में लंबित है। अभी यह जो हल्ला हुआ है, पिछले कुछ दिनों में, वह क्या है? मैंने बहस की थी कि चार्जशीट निरस्त है। क्यों निरस्त है, क्योंकि ईडी में लिखा है कि वो डिपार्टमेंट, वो यूनिट जो सरकारी यूनिट हो, ऑफिसर एम्पावर्ड... सिर्फ वही कंप्लेंट कर सकता है।

अब नेशनल हेराल्ड मामले में विचित्रता यह है कि किसी ईडी, किसी पुलिस, किसी एफआईआर में रजिस्टर नहीं हुआ था, सिर्फ सुब्रह्मण्यम् स्वामी जी कोर्ट गए थे, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट की थी, उस प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर केस शुरू हुआ और कुछ समय बाद स्वयं सुब्रह्मण्यम् स्वामी जी ने उस प्राइवेट कंप्लेंट को अपने आप... खुद जाकर हाई कोर्ट से स्टे करवा दिया, यानी अपनी कंप्लेंट को स्टे करवा दिया।

तो ये मूल बात समझने की है आपके दर्शकों को कि कंप्लेंट एक सिर्फ प्राइवेट थी, सरकारी कोई कंप्लेंट थी नहीं कभी नेशनल हेराल्ड में और वो कंप्लेंट भी सुब्रह्मण्यम् स्वामी ने स्टे करवा रखी थी। तो मैंने दलील यह दी थी करीब चार महीने पहले कि जब कोई सरकारी कंप्लेंट नहीं है तो ईडी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ईडी के एक्ट में लिखा है कि कंप्लेंट उस ऑफिसर द्वारा जो एम्पावर्ड है, वही कर सकता है, सुब्रह्मण्यम् स्वामी ऑफिसर नहीं हैं पुलिस के।

अब यह बड़ा lacuna है, जिससे एक पूरी इमारत जो बनाई गई है... वो गिर सकती थी, वो निर्णय अभी तक रिजर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि उस गैप को, उस बेवकूफी को, कोई प्रेडिकेट ऑफेंस और कोई एफआईआर ना होने को ठीक करने के लिए ये अभी नवंबर में नई एफआईआर दर्ज की गई और इसके आधार पर अब एक और ECIR की जाएगी, क्योंकि आधार इसको बनाया जाएगा, इसके पहले कोई आधार नहीं था सिवाय सुब्रह्मण्यम् स्वामी की एक कंप्लेंट के जो stayed थी।

तो आप समझ रहे हैं कि जल्दबाजी में द्वेष की भावना से काम करने से कितनी महामूर्खताएं होती हैं, कितनी मजाक होता है और किस प्रकार से नुकसान होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि इसको आपको देखना चाहिए सही परिप्रेक्ष्य में।

बीजेपी की राजनीति है- विपक्ष को थकाओ, झूठ को सजाओ और एजेंसियों को नचाओ। बीजेपी का नया नारा है- ना सबूत, ना तर्क, सिर्फ टारगेट। और टारगेट हम जानते हैं कौन है।

दोस्तों- 'ना पैसा, ना धोखा, ना कमाई'... मैंने अभी बताया पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, किसी ने धोखा करने की कंप्लेंट नहीं की... तो 'ना पैसा, ना धोखा, ना कोई कमाई... फिर भी बीजेपी ने मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी बनाई'। यह अजीबोगरीब कहानी है, क्योंकि आपका उद्देश्य है- 'विपक्ष को डराओ, जनता को भरमाओ और एजेंसियों को दौड़ाओ'... और जहां नींव नहीं, वहां इमारत कैसे खड़ी होगी? कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं, कोई एफआईआर नहीं। इसलिए एक और मूर्खता का प्रयत्न किया जा रहा है, यह अभी वाली एफआईआर फाइल करके। इसमें अलग-अलग खामियां क्या होंगी, वह आपको बाद में मालूम पड़ेगीं कोर्ट-कचहरी में, लेकिन आज यह है।

मैं एक बात से खत्म करना चाहता हूं- 'आवाज को दबाओगे, तो वो और बुलंद होगी'... ये नेशनल हेराल्ड का भी नारा रहा है, ब्रिटिश टाइम में। 'सच को मिटाओगे, तो वो और प्रचंड होगा'... क्योंकि हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, बीजेपी को जवाब कानून देगा, समय देगा और जनता देगी।

Dr Abhishek Manu Singhvi said- I am not going to repeat the transactions, the facts, the sequence I have explained is the same and you can understand it very well in the simple Hindi I have spoken. But I want to say on those facts, which I am not repeating, this is a bizarre situation- no crime, no cash, no trail to find, the BJP still conjures a case of its own twisted mind. If justice is blind, then ED is colour- blind. It only sees one colour- the opposition colour.

I have demonstrated to you in Hindi, it's a case with no money movement, no movement of immovable property, no mischief… yet the ED in its febrile imagination sees money laundering. Today, fiction has found a uniform. If vendetta was a syllabus, the BJP would graduate with honours- from a private complaint to a public circus. The National Herald case is the BJP's recycled obsession… not a rupee moved, not an inch of property changed hands, but the BJP manufactures the crime where none exists.

So, friends I end, this is not the National Herald case, this is the 'National Harassment' case and you can follow the selectivity- you, the BJP… you, the ED… your selectivity is summons for political rivals, safety for friends… the selective justice never ends.

On a question that how will you reply it, how will you take it forward, Dr Abhishek Manu Singhvi said- I have given the reply in the public domain. This is taking it forward to the Janta Janardan. It will be taken forward at all fora and obviously, the next forum will be the courts, the third forum is always Parliament. So, there are enough democratic forums… that's the only thing you can do in democracy, nothing else.

Sd/-
Secretary
Communication Deptt.
AICC